



2026:AHC: 56257

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 7751 वर्ष 2026

जितेंद्र यादव एवं 11 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार ओझा, विवेक सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि असावधानीवश प्रार्थना का गलत उल्लेख हो गया है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को सुनवाई के दौरान संशोधन आवेदन को सम्मिलित करने और उसे सही करने की अनुमति दी जाती है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता पंकज कुमार ओझा और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री करुणाकर सिंह को सुना गया।
4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन उप-जिला मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.), सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस द्वारा केस संख्या 9302/2025 में पारित विवादित नोटिस-सह-आदेश दिनांक 19.12.2025 को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 107/16 / सीआर.पी.सी. की धारा 151 के तहत आदेश पारित किया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित नोटिस-सह-आदेश दिनांक 19.12.2025 तथ्यों, परिस्थितियों और कानून की स्थिति पर विचार किए बिना, तथा नोटिस जारी करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 126, 135 के तहत आवश्यक मामले के तथ्यों और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिस्थितियों के प्रति अपनी संतुष्टि का कोई कारण बताए बिना पारित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवादित नोटिस-सह-आदेश छपे हुए प्रोफार्मा पर पारित किया गया है।

6. विवादित आदेश को चुनौती देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आदेश मुद्रित प्रपत्र पर दिया गया है, जिसमें आरोपी का नाम, मुकदमा अपराध संख्या और धारा हाथ से भरी गई है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **सिया नंद त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में **1994 क्रिमिनल लॉ जज 1298** में प्रकाशित निर्णय और दिल्ली उच्च न्यायालय के **तविंदर कुमार और अन्य बनाम राज्य** मामले में **1990 क्रिमिनल लॉ जज 40** में प्रकाशित निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायालय के **मधु लिमये बनाम एसडीएम मुंगेर (2); एआईआर 1971 एससी 2486** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें धारा 107/116 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने के संबंध में कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं।

8. इस न्यायालय के **अंकित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जेआईसी 2010 (1) 432** के फैसले पर भरोसा करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि चुनौती दिया गया आदेश मुद्रित प्रोफार्मा पर होने के कारण स्पष्ट रूप से न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है और इसलिए, केवल इसी आधार पर इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है कि चुनौती दिया गया आदेश मुद्रित प्रोफार्मा पर पारित किया गया है और इसलिए, **अंकित (उपरोक्त)** मामले में दिए गए निर्णय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मजिस्ट्रेट को एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

10. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन भी किया है।

11. अभियुक्त को सम्मन जारी करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति पेपर बुक के पृष्ठ-27 पर अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है। उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह एक टाइप किया हुआ प्रोफार्मा है जहाँ केवल केस संख्या, पक्षों के नाम, धारा, तारीख और अगली तारीख की जानकारी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तलेख में भरी जानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि छपे हुए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रोफार्मा के खाली स्थानों को किसी न्यायालय कर्मचारी द्वारा भरा गया है और उप-जिला मजिस्ट्रेट, सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस ने उसके बाद केवल अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मजिस्ट्रेट ने बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया है।

12. सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा मुद्रित प्रोफार्मा पर आदेश पारित करने की ऐसी प्रथा को अस्वीकार करने वाले कानून के बावजूद, यह देखना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान मामले में आवेदक को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा एक ऐसे आदेश द्वारा तलब किया गया है जिसमें न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना मुद्रित प्रोफार्मा पर रिक्त स्थान भरे गए हैं। इस प्रकार के आदेश को इस न्यायालय द्वारा **अंकित (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए पहले ही अमान्य घोषित किया जा चुका है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

"8. ...यद्यपि इस न्यायालय ने मेघ नाथ गुप्ता और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2008 (62) एसीसी 826 के मामले में यह माना है, जिसमें उप मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात बनाम रोशन लाल अग्रवाल, 2003 (4) एसीसी 686 (एससी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मोहन मीकिन्स, 2000 (2) जेआईसी 159 (एससी): एआईआर 2000 एससी 1456 और कांति भद्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2000 (1) जेआईसी 751 (एससी): 2000 (40) एसीसी 441 (एससी) के मामलों का संदर्भ दिया गया है, कि मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते समय विस्तृत तर्क सहित आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल मुद्रित प्रपत्र में रिक्त स्थान भरकर संज्ञान लेने का आदेश पारित किया जा सकता है। किसी भी न्यायिक आदेश को पारित करते समय, जिसमें आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश भी शामिल है, मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते समय विस्तृत तर्क सहित आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आरोपपत्र पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करना न्यायालय के लिए आवश्यक है और संज्ञान लेने का आदेश भी यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जा सकता। अतः, विवादित आदेश को रद्द किया जाना



चाहिए और न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए आरोपपत्र पर नए सिरे से आदेश

पारित करने के लिए मामले को निचली अदालत में वापस भेजा जाना चाहिए।"

13. उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना मुद्रित प्रपत्र पर रिक्त स्थान भरकर आदेश पारित करना निंदनीय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। किसी आपराधिक मामले में आरोपी को समन करना एक गंभीर मामला है और आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने तथ्यों के साथ-साथ लागू कानून पर भी विचार किया है।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है। उप-जिला मजिस्ट्रेट, सिकंदराराऊ, हाथरस द्वारा पारित विवादित नोटिस-सह-आदेश दिनांक 19.12.2025 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। उप-जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के बाद नया आदेश पारित करें।

(न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी)

17 मार्च, 2026

ईशान